Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

दिसंबर 2022 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- अल्मोड़ा के लक्ष्यसेन को मिला अर्जुन अवॉर्ड 3
- 'पोल्ट्री वैली योजना' की हुई शुरुआत 3
- उत्तराखंड में खुलेगा पहला सरकारी ड्रोन संस्थान व रिपेयरिंग सेंटर 4
- राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन 5
- उत्तराखंड के पहाड़ों में टनल पार्किंग के लिये 12 जगह तय 5
- केदारनाथ की तर्ज पर महासू देवता व जागेश्वर मंदिर का बनेगा मास्टर प्लान 6
- वरिष्ठ पत्रकार व राज्य आंदोलनकारी योगेश भट्ट बने राज्य सूचना आयुक्त 6
- इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देहरादून की अर्चना ने भाला फेंक में जीता गोल्ड 7
- प्रदेश में खुलेंगे 100 आँचल कैफे, उत्पादों की होगी मार्केटिंग 7
- वनाग्नि रोकने के लिये 500 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान 7
- उत्तराखंड में जल्द खुलेगा नैक का क्षेत्रीय कार्यालय 8
- उत्तराखंड के टूर ऑपरेटरों के लिये 'मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम' का एलान 8
- राष्ट्रपति ने उत्तराखंड में किया 2001.94 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास 9
- उत्तराखंड में महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार 9
- देहरादून के धाकड़ बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन भारतीय टेस्ट टीम में शामिल 10
- उत्तराखंड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित सिद्धदोष बंदियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के लिये) स्थायी नीति, 2022 की अधिसूचना जारी 10
- उत्तराखंड में जंगलों की आग बुझाने के लिये ग्रामीणों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि 11
- उत्तराखंड में एम्स और मेडिकल कॉलेजों से जुड़ेंगे हेल्थ वेलनेस सेंटर 11
- कॉलेजों में प्रोफेसर-छात्रों की हाजिरी के लिये आएगा जियो फेंसिंग सिस्टम 12
- रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे वीरता चक्र विजेता और वीर नारि 12
- कृषि कार्य के दौरान मौत पर मिलेगा डेढ़ लाख मुआवज़ा 13
- रायपुर और हल्द्वानी कॉलेज में सबसे पहले शुरू होगी जियो फेंसिंग हाजिरी 13
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को मिला अटल निर्मल नगर पुरस्कार 14
- टिहरी झील में पहली बार होगी नेशनल वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता 14
- उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा नई हाइड्रो पावर पॉलिसी की मंज़ूरी सहित लिये गए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय 15
- उत्तराखंड राज्य पार्किंग (स्थल चयन, निर्माण एवं संचालन इत्यादि) नियमावली, 2022 को मंज़ूरी 16
- प्रदेश में जल्द लागू होगी रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना 17
- राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंज़ूरी दी 17
- देहरादून में जुटेंगे सुरंग निर्माण से जुड़े दुनिया के 600 विशेषज्ञ 17
- प्रदेश में एक हज़ार गाँव बनेंगे सोलर ग्राम 18
- उत्तराखंड के पाँच अफसरों को मिला उत्कृष्ट ज़िलाधिकारी सम्मान 18
- हेलीकॉप्टर से पर्यटक कर सकेंगे अब हिमालय दर्शन 19
- आचार्य पं. इंदु प्रकाश को मिला 'लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान' 20
- मुख्यमंत्री को मिला 'स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान-2022' 20
- सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करेगा एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की का 'स्वस्थ गर्भ' एप 20
- राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ 21
- केंद्र सरकार खरीदेगी उत्तराखंड का मंडुवा 22
- पर्यटन को लेकर देशभर में छाया उत्तराखंड, चारधाम और कांवड़ यात्रा में बना नया रिकॉर्ड 22

नोट :

उत्तराखंड

अल्मोड़ा के लक्ष्यसेन को मिला अर्जुन अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

30 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी शटलर लक्ष्य सेन को अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 प्रदान किये। इन पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार-2022; द्रोणाचार्य पुरस्कार-2022; अर्जुन पुरस्कार-2022; ध्यानचंद पुरस्कार-2022; तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार-2021; राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार-2022 और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी-2022 शामिल हैं।
- लक्ष्य सेन का जन्म 16 अगस्त, 2001 को अल्मोड़ा के तिलकपुर वार्ड में हुआ था। लक्ष्य सेन ने चार साल की छोटी सी उम्र से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था।
- लक्ष्य के पिता डीके सेन भारतीय खेल प्राधिकरण में बैडमिंटन कोच रहे हैं और वर्तमान में प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी बंगलुरु में प्रशिक्षण दे रहे हैं।
- लक्ष्य सेन अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 26 पदक जीत चुके हैं। इनमें से 16 स्वर्ण पदक हैं। लक्ष्य सेन के बड़े भाई चिराग सेन भी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चिराग जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में नंबर दो रह चुके हैं।
- लक्ष्य ने अर्जुन अवार्ड अपने दादा स्व. सीएल सेन को समर्पित किया। लक्ष्य के दादा स्व. सीएल सेन बैडमिंटन के बेहतरीन खिलाड़ी थे। अपने समय में उन्होंने वेटरन में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की कई प्रतियोगिताएँ जीतीं थीं। उन्होंने अल्मोड़ा में बैडमिंटन खेल को बढ़ावा दिया था। अल्मोड़ा में उन्हें बैडमिंटन का भीष्म पितामह के नाम से भी जाना जाता है।

'पोल्ट्री वैली योजना' की हुई शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

1 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने संयुक्त रूप से किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिये 'पोल्ट्री वैली योजना'की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि सहकारिता और पशुपालन विभाग ने मिलकर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिये 'पोल्ट्री वैली योजना' पहल की है। योजना से तीन साल में पाँच हज़ार युवकों और महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
- यूकेसीडीपी निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार पोल्ट्री किसानों की आय को दोगुना करेगी। अभी उत्तराखंड में मुर्गियाँ नजीबाबाद और बिजनौर से आ रही हैं। सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर पोल्ट्री किसानों को सहायता दी जाए ताकि उनकी आमदनी दोगुनी हो और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रुक सके। अभी चकराता में पोल्ट्री का कार्य शुरू हुआ। इसके बाद अब यह काम पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
- पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि इस योजना के लागू होने पर युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
- सहकारिता और पशुपालन विभाग के सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि इस योजना के तहत परियोजना अवधि वित्तीय वर्ष 2022 से 2025 के लिये 5000 लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 182 करोड़ की इस योजना में लाभार्थियों को मुफ्त चूजे और ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।

नोट :

उत्तराखंड में खुलेगा पहला सरकारी ड्रोन संस्थान व रिपेयरिंग सेंटर

चर्चा में क्यों ?

2 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में ड्रोन की मदद से विभागों के काम आसान करने और युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिये राज्य सरकार ड्रोन संस्थान खोलेगी। इससे ड्रोन के निर्माण, संचालन और मरम्मत की राह आसान हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने उत्तराखंड में ड्रोन के निर्माण से लेकर रिपेयरिंग, निवेशकों को आकर्षित करने के लिये ड्रोन पॉलिसी बनाकर शासन को भेजी है। पॉलिसी में तेलंगाना की ड्रोन पॉलिसी की तर्ज पर कई अहम बदलाव किये गए हैं। ड्रोन पॉलिसी पर सरकार जल्द कैबिनेट में निर्णय ले सकती है।
- इसके तहत ड्रोन कॉरिडोर के अलावा सरकारी ड्रोन संस्थान, रिपेयरिंग सेंटर खोलने का भी प्रावधान किया जा रहा है।
- जानकारी के अनुसार ऐसा ड्रोन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा जो युवाओं को ट्रेनिंग संग सरकारी विभागों में ड्रोन की जरूरतों को चिह्नित करेगा। इसकी मदद से विभाग ड्रोन से अपने काम आसान कर सकेंगे। वहीं, प्रदेश में ड्रोन रिपेयरिंग सेंटर भी खोले जा सकेंगे।
- ड्रोन पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है कि ड्रोन निर्माता और सेवा प्रदाता अपने उत्पाद का निशुल्क ट्रायल कर सकेंगे। इसके लिये फ्री फ्लाई ज़ोन तैयार किया जाएगा। ड्रोन के टेकऑफ और लैंडिंग के लिये एयरस्ट्रिप, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल लैब, हैंगर, ट्रेनिंग, हेलीपैड, सपोर्ट स्पेशलिस्ट, रिचार्जिंग स्टेशन आदि की सुविधा दी जाएगी।
- पॉलिसी में यह भी प्रावधान किया गया है कि सरकार एक फेसिलिटेशन सेल खोलेगी जिसमें ड्रोन के लाइसेंस और पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। सरकार का मकसद है कि डीजीसीए के नियमों का अनुपालन सख्ती से हो और ड्रोन को बढ़ावा भी मिले। यह सेल ड्रोन निर्माण के परमिट में भी मदद करेगी।
- ड्रोन की सुरक्षित उड़ान को लेकर रिटायर्ड आर्मी अफसरों, जवानों और पुलिसकर्मियों की मदद से स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह बोर्ड सेना के अपने अनुभवों के आधार पर ड्रोन की सुरक्षित उड़ान को लेकर जरूरी सलाह देगा।
- प्रदेश के सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थानों में भी आईटीडीए की मदद से युवाओं को ड्रोन संचालन और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जाएगी। एरियल फोटोग्राफी, सर्विलांस, रिमोट सेंसिंग को लेकर विशेष प्रोग्राम संचालित किये जाएंगे। ड्रोन इंजीनियरिंग में काम कर रहे विश्वविद्यालय से भी समझौता किया जाएगा। ड्रोन के रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा।
- निर्माताओं को लाभ-
  - एक निश्चित अवधि तक निर्माताओं को एसजीएसटी में 100 प्रतिशत छूट दी जा सकती है।
  - वह अधिकतम पाँच करोड़ रुपए तक निवेश कर सकते हैं।
  - उन्हें प्रोजेक्ट में 25 फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम तीन करोड़ तक होगी।
  - 10 साल तक लीज़ या किराये पर 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
  - ज़मीन खरीदने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट जैसे प्रावधान।
- सेवा प्रदाताओं को लाभ-
  - 50 लाख तक के निवेश पर 25 प्रतिशत सब्सिडी,
  - पाँच लाख तक के लीज़ या किराये पर 30 प्रतिशत सब्सिडी,
  - कई प्रदर्शनियों में ड्रोन का स्टॉल लगाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  - इंटरनेट शुल्क में 100 प्रतिशत तक छूट,
  - राज्य सरकार की ओर से चिह्नित क्षेत्र में रिसर्च पर 10 लाख रुपए तक की ग्रांट मिलेगी।

नोट :

राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों ?

2 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया है। इनमें तीन गैर सरकारी संगठनों और सात गैर सरकारी सदस्यों को दो साल के लिये नामित किया गया है। इस संबंध में शासन की ओर से निर्देश जारी कर दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- वन सचिव विजय यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राज्य वन्यजीव बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। अधिनियम में दी गई व्यवस्था के तहत दो वर्ष के लिये सदस्यों को नामित किये जाने की राज्यपाल की ओर से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।
- गौरतलब है कि राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष वन मंत्री होते हैं। इसके अलावा राज्य के पुलिस महानिदेशक सहित कुल 15 पदेन सदस्य और 16 सदस्य राज्य सरकार की ओर से नामित किये जाते हैं। इसके अलावा तीन विधानमंडल दल के सदस्य, तीन गैर सरकारी संगठनों के सदस्य और सात सदस्य पारिस्थितिकी विज्ञानी, पर्यावरणविद एवं संरक्षण विज्ञानी नामित किये जाते हैं।
- राज्य वन्यजीव बोर्ड में नामित किये गए गैर सरकारी संस्थाएँ हैं-
  - डब्ल्यूडब्लयूएफ इंडिया, विश्व प्रकृति निधि, भारत
  - हिमालयन एनवायरनमेंट स्टडीज एंड कंजरवेशन आर्गेनाइजेशन (हेस्को), देहरादून
  - हिमालय एक्सन रिसर्च सेंटर, देहरादून
- राज्य वन्यजीव बोर्ड में नामित किये गए गैर सरकारी सदस्य हैं-
  - अनूप शाह, नैनीताल (जाने-माने फोटोग्राफर)
  - अनिल कुमार दत्त (सेवानिवृत्त आईएफएस)
  - बीएस बोनाल (सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक, वन्यजीव)
  - फैज आफताब, देहरादून
  - मंयक तिवारी, नैनीताल
  - संजय सोंधी, तितली ट्रस्ट, देहरादून
  - ओम प्रकाश भट्ट, सर्वोदय केंद्र चमोली
- विदित है कि वन विभाग की ओर से अत्तूबर में नए सदस्यों का शामिल करने का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया था।

उत्तराखंड के पहाड़ों में टनल पार्किंग के लिये 12 जगह तय

चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुमका ने बताया कि मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु के निर्देश पर चार ज़िलों में कुल 12 पहाड़ों को टनल पार्किंग के लिये चुना गया है। इनकी डीपीआर बनाई जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि हर साल लाखों पर्यटक उत्तराखंड आते हैं, लेकिन पहाड़ी ज़िलों में पार्किंग की समस्या विकराल है। पार्किंग की समस्या दूर करने के लिये मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु के निर्देशों पर टनल पार्किंग पर काम शुरू हुआ था।
- पार्किंग बनाने के लिये आरवीएनएल, यूजेवीएनएल, टीएचडीसी और एनएचआईडीसीएल को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।
- टनल पार्किंग के लिये पौड़ी में दो, टिहरी में छह, उत्तरकाशी में दो और नैनीताल में दो मिलाकर कुल 12 टनल पार्किंग की जगह तय की गई है।

नोट :

- जिन पर्वतीय जिलों में पार्किंग के लिये बड़ा मैदान उपलब्ध नहीं है, वहाँ पहाड़ों के भीतर ही टनल से पार्किंग का काम लिया जाएगा। ये पार्किंग ऐसी बनाई जाएंगी कि एक तरफ से वाहन पार्किंग के लिये घुसेगा और दूसरी सड़क पर बाहर निकल जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2025 तक प्रदेश में 50 बड़ी पार्किंग बनाने का लक्ष्य तय किया है। 2030 तक इनकी संख्या 100 तक हो जाएगी। इसमें निजी सहभागिता के लिये भी विशेष छूट के प्रावधान किये जा रहे हैं। इसके लिये शासन स्तर पर पार्किंग नीति की प्रक्रिया चल रही है, जो जल्द ही कैबिनेट में लाई जाएगी।

केदारनाथ की तर्ज पर महासू देवता व जागेश्वर मंदिर का बनेगा मास्टर प्लान

चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि केदारनाथ और बदरीनाथ धाम की तर्ज पर अब हनोल स्थित महासू देवता और अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर मंदिर के विकास के लिये मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जारी बयान में कहा कि केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण और बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। केदारनाथ व बदरीनाथ में हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है।
- गौरतलब है कि देहरादून जिले में हनोल स्थित महासू देवता और अल्मोड़ा के जागेश्वर मंदिर में लोगों की अटूट आस्था है। यहाँ देश के कई राज्यों से भी लोग दर्शन के लिये आते हैं।
- पर्यटन मंत्री ने कहा कि केदारनाथ व बदरीनाथ धाम के मास्टर प्लान में आईएनआई एजेंसी की सेवाएँ ली गई थी। महासू और जागेश्वर मंदिर का मास्टर प्लान बनाने के लिये आईएनआई को सिंगल सोर्स के माध्यम से अनुमति देने की प्रक्रिया चल रही है। अनुमति मिलते ही इन दोनों मंदिरों का मास्टर प्लान के अनुसार विकास कार्य किये जाएंगे।
- मास्टर प्लान बनने से दोनों ऐतिहासिक मंदिरों में यात्री सुविधाओं का सुनियोजित ढंग से विकास हो सकेगा।

वरिष्ठ पत्रकार व राज्य आंदोलनकारी योगेश भट्ट बने राज्य सूचना आयुक्त

चर्चा में क्यों ?

4 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को सूचना आयुक्त की ज़िम्मेदारी सौंपी है। उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने के दिन से अगले तीन साल तक रहेगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रभारी सचिव सुरेंद्र नारायण पांडेय की ओर से इस बाबत आदेश ज़ारी किये गए हैं।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनी चयन समिति ने शासन को प्राप्त आवेदनों के आधार पर उनका चयन किया है। समिति में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कैबिनेट मंत्री चंदनराम दास शामिल हैं।
- उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान छात्र जीवन में रहते हुए योगेश भट्ट ने सक्रिय आंदोलनकारी की भूमिका निभाई। स्टूडेंट्स एंड यूथ एलायंस (साया) के संचालनकर्त्ताओं में शामिल रहे भट्ट पर 'राज्य नहीं तो चुनाव नहीं' आंदोलन के दौरान गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। राज्य बनने के बाद भी तमाम मंचों पर उत्तराखंड से जुड़े सवालों पर योगेश की मुखरता निरंतर बनी रही।
- 90 के दशक में पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले योगेश भट्ट की पहचान प्रखर पत्रकार के रूप में भी बनी हुई है। उन्होंने कई समाचार पत्रों में काम करते हुए अलग पहचान बनाई। योगेश पत्रकार हितों के मुद्दे पर भी हमेशा मुखर रहे हैं। ये उत्तरांचल प्रेस क्लब में महामंत्री और अध्यक्ष का दायित्व भी निभा चुके हैं।

नोट :

इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देहरादून की अर्चना ने भाला फेंक में जीता गोल्ड

चर्चा में क्यों ?

3-4 दिसंबर, 2022 को कुआलालंपुर, मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देहरादून की अर्चना बिष्ट ने शॉटपुट (भाला फेंक) में स्वर्ण पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- ओएनजीसी में सहायक सुपरिनटेंडेंट के पद पर कार्यरत अर्चना बिष्ट वरिष्ठ भाजपा नेत्री एवं प्रदेश मंत्री महिला मोर्चा वंदना बिष्ट की छोटी बहन हैं।
- खेल के अलावा अर्चना बिष्ट सामाजिक कार्य भी करती हैं और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों फ्री कोचिंग भी देती हैं।
- उल्लेखनीय है कि अर्चना बिष्ट इससे पहले 2016 में ऑस्ट्रेलिया में प्रतिभाग कर चुकी हैं। अर्चना बिष्ट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन की लेवल वन कोच भी हैं। इनके द्वारा तैयार किये गए बच्चों ने इसी साल नेशनल एथलेटिक्स प्रतियोगिता गुवाहाटी में प्रतिभाग करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया था।

प्रदेश में खुलेंगे 100 आँचल कैफे, उत्पादों की होगी मार्केटिंग

चर्चा में क्यों ?

5 दिसंबर, 2022 को दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने देहरादून के घंटाघर स्थित एमडीडीए कॉम्पलेक्स में 'आँचल कैफे' का उद्घाटन करते हुए आँचल दूध से बने उत्पादों की मार्केटिंग और रोज़गार के लिये प्रदेश भर में इस तरह के 100 आँचल कैफे खोले जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि विभाग की ओर से आँचल कैफे बनाकर दिया जाएगा, जो कमीशन के आधार पर संचालित होगा। आँचल कैफे आवंटन में शहीदों के आश्रितों, राज्य आंदोलनकारी, दिव्यांग, महिलाओं, युवाओं को प्राथमिकता दी गई है।
- आँचल कैफे में लोगों को दूध के अलावा आइसक्रीम, दही, लस्सी, शेक, घी, पनीर समेत अन्य दुग्ध उत्पाद एक ही जगह पर उपलब्ध होंगे।
- विभागीय मंत्री ने कहा कि आँचल का पहला कैफे शहीद जगदीश प्रसाद की पत्नी कंचनी देवी को आवंटित किया गया है। दो माह के भीतर देहरादून के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर 10 आँचल कैफे और स्थापित किये जाएंगे।
- उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने भूसे में 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।

वनाग्नि रोकने के लिये 500 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान

चर्चा में क्यों ?

6 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने देहरादून में हुई बैठक में बताया कि राज्य में हर साल जंगलों में लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिये वन विभाग ने 500 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके लिये वन विभाग की ओर से फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन प्रोजेक्ट पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में वनाग्नि पर नियंत्रण के लिये कई उपाय सुझाए गए हैं। स्थानीय लोगों की भूमिका को अंकित कर उन्हें ट्रेनिंग तथा प्रोत्साहन राशि देने की बात कही गई है। इसके अलावा महिला और युवक मंगल दलों को भी इससे जोड़ने की चर्चा हुई।
- वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि अगले पाँच वर्षों के लिये तैयार की गई योजना लागू होने के बाद वन महकमा हर साल 100 करोड़ रुपए वनाग्नि नियंत्रण पर खर्च कर सकेगा। ज़रूरत पर वनाग्नि बुझाने के लिये हेलीकॉप्टर तक का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

नोट :

- इस एक्शन प्लान में ग्रामीणों के साथ फायर वॉचर को भी आग बुझाने के लिये पहली बार पैसा दिया जाएगा। वन मुख्यालय के मास्टर कंट्रोल रूम को अत्याधुनिक बनाने के लिये कई उपकरणों की खरीद का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा मौसम विज्ञान विभाग की मदद से ऑटोमेटेड वेदर सेंसर लगाने, मॉडल क्रू स्टेशन, एडब्ल्यूएस स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, वायरलेस नेटवर्क मज़बूत बनाने के लिये सामुदायिक संस्थानों को योजना से जोड़ा जाएगा।
- उन्होंने बताया कि चीड़ की पत्तियाँ (पिरूल) वनाग्नि का प्रमुख कारण बनती हैं, जबकि पिरूल से कई उत्पाद भी बनाए जाते हैं। पिरूल से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वह ज़रूरत के अनुसार जंगलों से पिरूल उठा सकें।
- उल्लेखनीय है कि प्रदेश में प्रतिवर्ष वनाग्नि की करीब दो हज़ार घटनाएँ होती हैं। इनमें हर साल करीब तीन हज़ार हेक्टेयर जंगल जलता है। 2022 में अब तक वनाग्नि की 2,186 घटनाएँ हुई हैं, जबकि 3425 हेक्टेयर जंगल को नुकसान पहुँचा।
- विदित है कि वन विभाग की ओर से इस एक्शन प्लान के लिये तैयार प्रस्ताव पर प्राथमिक तौर पर चर्चा कर ली गई है। इसमें कुछ अन्य बिंदुओं को जोड़ने के लिये कहा गया है। फाइनल ड्राफ्ट तैयार होने के बाद मंजूरी के लिये केंद्र को भेजा जाएगा।

उत्तराखंड में जल्द खुलेगा नैक का क्षेत्रीय कार्यालय

चर्चा में क्यों ?

7 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के देहरादून के डीआईटी कॉलेज में आयोजित उच्च शिक्षा चिंतन शिविर मं। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) बंगलूरू के निदेशक प्रो.एससी शर्मा ने उत्तराखंड में शीघ्र ही अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की क्वालिटी फैक्ट सीट एवं उच्च शिक्षा पर आधारित एक पुस्तक का भी विमोचन किया।
- चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई नए कार्य किये जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के माध्यम से युवा स्वयं नौकरियाँ देने वाले बन सकेंगे।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नैक का क्षेत्रीय कार्यालय राज्य के साथ-साथ अन्य निकटवर्ती राज्यों के लिये भी बहुत बड़ा उपहार सिद्ध होगा।
- राज्य उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान को संसाधनों की उपलब्धता, फैकल्टी की तैनाती, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ एवं अन्य गतिविधियों के आधार पर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ग्रेडिंग दी जाएगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए निकट भविष्य में प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में नैक प्रशिक्षण की पाँच कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- इस अवसर पर राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने देश के तीन प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी किये। जिन संस्थानों के साथ करार किया गया, उनमें भारतीय उद्यमिता संस्थान अहमदाबाद, एडुनेट एवं अमृता विश्व विद्यापीठम शामिल हैं।
- भारतीय उद्यमिता संस्थान प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में उद्यमिता, रोज़गार कौशल और गुणवत्तापरक शिक्षा में सहयोग प्रदान करेगा वहीं, एडुनेट के माध्यम से उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं एवं फैकल्टी को नि:शुल्क तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जबकि अमृता विश्व विद्यापीठम अपने मटेरियल साइंस केंद्र एवं वर्चुअल लैब के माध्यम से विज्ञान विषय में शोध एवं अन्य गतिविधियों में सहयोग करेगा।

उत्तराखंड के टूर ऑपरेटरों के लिये 'मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम' का एलान

चर्चा में क्यों ?

8 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने अगले साल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में विदेशी पर्यटकों को लाने के लिये राज्य में टूर ऑपरेटरों के लिये 'मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम' का एलान किया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड में योग के प्रति देश दुनिया को आकर्षित करने के लिये पर्यटन विभाग की ओर से हर साल ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया जाता है। महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा विदेशी पर्यटक भागीदार बनें, इसकी उद्देश्य से पर्यटन विभाग ने टूर ऑपरेटरों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने हेतु 'मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम' की घोषणा की गई है।
- इस स्कीम के तहत अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की बुकिंग करने वाले टूर ऑपरेटरों को प्रति पर्यटक 10 हजार रुपए और अधिकतम पाँच लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह वित्तीय प्रोत्साहन टूर ऑपरेटरों को विदेशी पर्यटकों को योग महोत्सव में लाने के एवज में दिया जाएगा।
- योजना का लाभ इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, पर्यटन मंत्रालय और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद से मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर्स को मिलेगा। पर्यटकों को लाने वाले मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटरों को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मार्केटिंग प्रमोशन के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
- इसके अलावा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में भाग लेने वाले विदेशी मेहमानों की बुकिंग व पंजीकरण का विवरण, उनके पासपोर्ट व वैध वीजा की प्रतियाँ और उनके लिये होटल बुकिंग आदि दस्तावेज़ यूटीडीबी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।

राष्ट्रपति ने उत्तराखंड में किया 2001.94 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

8 दिसंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में राज्य के लिये 2001.94 करोड़ रुपए की नौ विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 528.35 करोड़ रुपए की तीन योजनाओं का लोकार्पण और 1473.59 करोड़ की छह योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति ने 330.64 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सोबन सिंह जीना राजकीय मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा, पिटकुल की ओर से हरिद्वार ज़िले के पदार्था में 84 करोड़ रुपए की लागत से 132 केवी के आधुनिक तकनीक के बिजली घर, इससे संबंधित लाइन का निर्माण, ज़िला रुद्रप्रयाग में 113.71 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4.5 मेगावाट की कालीगंगा-द्वितीय लघु जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया है।
- इसके अलावा उन्होंने 306 करोड़ रुपए की लागत से चीला पावर हाउस के 144 मेगावाट की योजना का रेनोवेशन कार्य, देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 204.46 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्पलेक्स के ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण, 131 करोड़ की लागत से हरिद्वार के मंगलौर में 220 केवी सब स्टेशन, 750 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून के मुख्य मार्गों की ओवर हेड एचटी एवं एलटी विद्युत लाइनों को भूमिगत किये जाने का कार्य, 32.93 करोड़ की लागत से राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्रनगर में दूसरे चरण का निर्माण कार्य और चंपावत के टनकपुर में 49.20 करोड़ की लागत से आधुनिक अंतरराज्यीय बस टर्मिनल का शिलान्यास किया।

उत्तराखंड में महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार

चर्चा में क्यों ?

8 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने महिला नीति के ड्राफ्ट पर सचिवालय में हुई अधिकारियों की बैठक के बाद बताया कि प्रदेश में पहली बार महिलाओं के लिये नीति बनने जा रही है। राज्य महिला आयोग की ओर से महिला नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे अगले साल आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जारी किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- कुसुम कंडवाल ने बताया कि कई विभागों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है। खासकर पहाड़ की महिलाओं को केंद्र में रखते हुए ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। महिला नीति में एकल महिलाओं के लिये विशेष व्यवस्था करने पर ज़ोर दिया गया है।

नोट :

- एकल महिलाओं के संगठनों को ब्लॉक और ज़िला स्तर पर मज़बूती देने के लिये कई योजनाएँ प्रस्तावित हैं। इंदिरा आवास योजना और मनरेगा में भी एकल महिलाओं के लिये कुछ फीसदी आरक्षण की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- बैठक में बताया गया कि महिलाओं को आगे बढ़ाने, उनके विकास और सशक्तीकरण के लिये कई सरकारी योजनाओं में बदलाव की ज़रूरत है। खासकर समाज कल्याण विभाग की शादी-अनुदान की योजना में बदलाव होना चाहिये। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की बेटियों एवं सामान्य वर्ग में विधवा महिला की बेटी की शादी के लिये 50 हज़ार रुपए का अनुदान दिया जाता है। शादी की लिये अनुदान के बजाए बेटियों की शिक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिये सहयोग दिया जाना चाहिये।
- राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि वन पंचायतों में महिलाओं के लिये 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये।

देहरादून के धाकड़ बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन भारतीय टेस्ट टीम में शामिल

चर्चा में क्यों ?

11 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के देहरादून के धाकड़ बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को भारतीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि कप्तान रोहित शर्मा के चोटिल होने के कारण बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिये उनको टीम इंडिया में शामिल किया गया है। बता दें कि अभी तक उन्हें भारत के लिये अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने यानी पदार्पण करने का मौका नहीं मिल पाया है।
- क्रिकेट के जानकारों का कहना है कि अभिमन्यु ने बांग्लादेश के खिलाफ अंडर-19 में कप्तान के रूप में लगातार दो शतक लगाकर मजबूत दावेदारी पेश की थी। उन्हें इसी प्रदर्शन का इनाम मिला है।
- ज्ञातव्य है कि 27 वर्षीय अभिमन्यु ने मात्र सात वर्ष की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। अभिमन्यु ने प्रथम श्रेणी में 78 मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम 3376 रन हैं। उनका औसत 2 और स्ट्राइक रेट 82.2 है। 28 टी-20 मैचों में 38.3 की औसत और 121.5 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 728 रन बनाए हैं।

उत्तराखंड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित सिद्धदोष बंदियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के लिये) स्थायी नीति, 2022 की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

12 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित सिद्धदोष बंदियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के लिये स्थायी नीति, 2022 की अधिसूचना जारी की।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड राज्य (न्यायालयों द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित सिद्धदोष बंदियों की सजामाफी/समयपूर्व मुक्ति के लिये) स्थायी नीति, 2022 के अंतर्गत आजीवन कारावास में बंद महिला और पुरुष कैदी समान सजा के बाद रिहा हो सकेंगे। रिहाई के लिये उन्हें अच्छे आचरण, अपराध की प्रकृति और आयु की कसौटी पर परखा जाएगा। उनकी 50 हज़ार रुपए के निजी मुचलके पर रिहाई हो सकेगी।
- अपराध की प्रकृति के साथ बंदियों की रिहाई पर निर्णय होगा। यदि कोई बंदी गलती से रिहा हो जाता है तो उसे दोबारा जेल भेजा जा सकेगा। 13 से अधिक गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बंदियों को भी रिहाई मिल सकेगी।
- इस नीति के तहत आजीवन कारावास के तहत अब अधिकतम 14 साल की सजा होगी। अभी तक महिलाओं के लिये 14 साल और पुरुषों के लिये 16 साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन अब ऐसे सिद्धदोष महिला व पुरुष बंदी जिनकी बिना पैरोल के 14 साल और पैरोल के साथ 16 वर्ष की सजा पूरी हो गई है, उनकी सजा माफ हो सकेगी।
- इसी तरह 70 वर्ष से अधिक आयु के बगैर पैरोल वाले बंदी 12 वर्ष और पैरोल पर रहे 14 वर्ष और 80 वर्ष से अधिक उम्र के कैदी बगैर पैरोल 10 वर्ष और पैरोल के साथ 12 वर्ष में रिहा हो सकेंगे।

नोट :

- नीति के अनुसार ऐसे मामलों पर विचार करने के लिये प्रमुख सचिव या सचिव गृह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। इस कमेटी में प्रमुख सचिव या सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी, प्रमुख सचिव या सचिव गृह और अपर सचिव गृह (कारागार) सदस्य होंगे, जबकि महानिरीक्षक कारागार सदस्य सचिव होंगे।

उत्तराखंड में जंगलों की आग बुझाने के लिये ग्रामीणों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

चर्चा में क्यों ?

12 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन के मुख्य वन संरक्षक निशांत वर्मा ने बताया कि वनाग्नि पर काबू पाने के लिये जन सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में वनाग्नि प्रबंधन समितियों का गठन किया जा रहा है। इसके लिये उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- निशांत वर्मा ने बताया कि जंगलों की आग बुझाने के लिये ग्रामीणों को प्रोत्साहन राशि देने के प्रथम चरण में चीड़ बाहुल्य वन प्रभागों को योजना में लिया जा रहा है। इसमें वन पंचायतों का क्षेत्र भी शामिल होगा। इसके लिये वनाग्नि प्रबंधन समितियों का गठन किया जा रहा है।
- गौरतलब है कि राज्य के वनों में प्रतिवर्ष औसतन 2000 से 2200 वनाग्नि की घटनाएँ होती हैं। इनमें हर साल करीब तीन हज़ार हेक्टेयर से अधिक जंगल जल जाता है। वर्ष 2022 में अब तक वनाग्नि की 2,186 घटनाएँ सामने आ चुकी हैं। इनमें 05 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुँचा, जबकि इससे पहले वर्ष 2021 में वनाग्नि की 2,780 वनाग्नि की घटनाएँ दर्ज की गई थीं।
- उन्होंने बताया कि बीते सालों में सर्दियों के मौसम में भी वनाग्नि की घटनाएँ हो चुकी हैं। इस समस्या से पार पाने के लिये पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर वनाग्नि प्रबंधन समितियों का गठन किया जा रहा है। अभी तक तीन वन प्रभागों अल्मोड़ा, टिहरी और गोपेश्वर में 48 वनाग्नि प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है। समिति में ग्रामीणों के साथ ग्राम पंचायतों, वन पंचायतों के सरपंच और वनकर्मियों को शामिल किया जा रहा है।
- विदित है कि राज्य में कुल 11 हज़ार 300 वन पंचायतें हैं। इन्हें अस्थायी तौर पर आसपास के जंगलों की वनाग्नि से सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी।
- निशांत वर्मा ने बताया कि जंगल में आग लगने पर यदि यह समितियाँ तत्परता दिखाते हुए उसे बुझा देती हैं, तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि कितनी होगी, इस पर अभी विचार किया जा रहा है। राज्य में वनाग्नि पर काबू पाने के लिये प्रतिवर्ष करीब 15 करोड़ रुपए के आसपास खर्च किये जाते हैं।

उत्तराखंड में एम्स और मेडिकल कॉलेजों से जुड़ेंगे हेल्थ वेलनेस सेंटर

चर्चा में क्यों ?

12 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून के आईटीडीए सभागार में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस पर हुए कार्यक्रम में बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराने के लिये प्रदेश में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को एम्स और राजकीय मेडिकल कॉलेजों से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवा का विस्तार होगा।

प्रमुख बिंदु

- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को सभी आधुनिक सुविधाओं से जोड़कर सीएचओ, एएनएम एवं आशा की तैनाती की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को 50 दिन में 826 एएनएम और 100 दिन में 1,500 नर्सें मिल जाएंगी। हेल्थ एवं वेलनेस सेंटरों में जल्द ही 664 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के साथ ही योग प्रशिक्षकों की भी नियुक्ति की जा रही है।
- देहरादून नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि 2025 तक प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी।
- प्रभारी सचिव स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश में टेलीमेडिसिन सेवा बेहतर कार्य कर रही है, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र के हज़ारों लोगों को मिल रहा है। इस सेवा को मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टरों जोड़ते हुए प्रभावी बनाया जाएगा।

नोट :

कॉलेजों में प्रोफेसर-छात्रों की हाजिरी के लिये आएगा जियो फेंसिंग सिस्टम

चर्चा में क्यों ?

14 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के उच्च शिक्षा एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि प्रदेश के दूर दराज के पर्वतीय इलाकों के डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों और छात्रों की पहुँच सुनिश्चित करने के लिये जियो फेंसिंग हाजिरी सिस्टम लागू होगा। भविष्य में यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि प्रदेश के कुछ कॉलेजों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत की जा रही है। जियो फेंसिंग हाजिरी से मॉनिटरिंग आसान हो जाएगी। पायलट सफल रहा तो प्रदेशभर में इसे लागू किया जाएगा।
- विदित है कि इससे पहले परिवहन निगम अपने सभी बस अडन्में पर इसे लागू कर चुका है, जिसके तहत बस अड्डे की जियो फेंसिंग की गई है।
- दरअसल, प्रदेश के तमाम दुर्गम इलाकों के डिग्री कॉलेज ऐसे हैं, जहाँ शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति का आँकड़ा काफी कमतर रहता है। महीने में कुछ दिन जाकर शिक्षक अपनी हाजिरी पूरी कर लेते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिये ही जियो फेंसिंग हाजिरी सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू की गई है।
- उच्च शिक्षा विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने जा रहा है। इसके तहत जो भी शिक्षक या छात्र कॉलेज परिसर में प्रवेश करेगा तो उसके मोबाइल से ही उसकी हाजिरी लग जाएगी। इसके लिये मोबाइल जियो फेंसिंग के दायरे में आना जरूरी है।
- जब कोई छात्र या शिक्षक अपने मोबाइल के साथ कैंपस में प्रवेश करेंगे तो उन्हें इसमें डाउनलोड किया गया हाजिरी का ऐप खोलना होगा। यह ऐप केवल कॉलेज के भीतर यानी जियो फेंसिंग दायरे में आने पर ही काम करेगा। इस ऐप को खोलने के बाद उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे फीड करेंगे तो ही हाजिरी लग जाएगी और जैसे ही छात्र, शिक्षक उस कैंपस से बाहर जाएंगे, उनका रिकॉर्ड स्वत: ही अपडेट हो जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि जियो फेंसिंग सैटेलाइट आधारित प्रणाली है, जिसमें एक विशेष क्षेत्र की जियो फेंसिंग यानी बाउंड्री बना दी जाती है। इस दायरे में जो भी डिवाइस आएगी, वह रिकॉर्ड में आ जाएगी। जियो फेंसिंग के भीतर आने पर ही मोबाइल का वह ऐप काम करेगा जो कि इससे संबंधित होता है।

रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे वीरता चक्र विजेता और वीर नारि

चर्चा में क्यों ?

16 दिसंबर, 2022 को विजय दिवस पर गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के वीरता चक्र विजेता सैनिक और वीर नारियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा देने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश में शहीद द्वार और स्मारकों का निर्माण कार्य अब सैनिक कल्याण विभाग के जरिये होगा। पहले यह संस्कृति विभाग के माध्यम से होता था।
- उन्होंने कहा कि वर्ष 1971 के युद्ध में उत्तराखंड के 255 जवानों ने भारत माँ की रक्षा के लिये प्राणों का बलिदान दिया था। युद्ध में अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देने वाले प्रदेश के 74 सैनिकों को विभिन्न वीरता पदकों से नवाज़ा गया था।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य परिवारों के लिये राज्य सरकार विशेष योजनाएँ बना रही है ताकि एक सैनिक को युद्ध लड़ते समय परिवार की चिंता न हो। सैनिकों या उनके आश्रितों को मिलने वाली अनुदान राशि बढ़ाने से लेकर शहीदों के आश्रितों को राज्य सरकार की नौकरियों में वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है।

नोट :

- सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, उत्तराखंड में 1727 सैनिकों और सेना के अधिकारियों को वीरता चक्र मिला है। इनमें एक परमवीर चक्र, छह अशोक चक्र, 13 महावीर चक्र, 32 कीर्ति चक्र, चार उत्तम युद्ध सेवा मेडल, 102 वीर चक्र, 188 शौर्य चक्र, 36 युद्ध सेवा मेडल, 847 सेना मेडल (वीरता), 198 मेंशन इन डिस्पैच, 70 सेना मेडल, 45 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 56 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 129 विशिष्ट सेवा मेडल विजेता शामिल हैं। वहीं, प्रदेश में वीर नारियों की संख्या वर्तमान में करीब 1100 है।
- गौरतलब है कि विजय दिवस भारतीय सेना के वीर जवानों के अदम्य साहस, शौर्य का प्रतीक है। इसी दिन वर्ष 1971 में पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सेना का यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था।

कृषि कार्य के दौरान मौत पर मिलेगा डेढ़ लाख मुआवज़ा

चर्चा में क्यों ?

16 दिसंबर, 2022 को विधानसभा स्थित कार्यालय में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की 35वीं बैठक में किसानों के हित में कई फैसले लिये गए। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर मिलने वाली मुआवज़ा राशि को एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इसके अलावा दुर्घटना से दोनों हाथ या दोनों पैर या फिर एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग होने पर मुआवज़े को 60 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख और एक अंग से दिव्यांग होने पर मुआवज़े को 30 हज़ार से बढ़ाकर 50 हज़ार रुपए करने का निर्णय लिया गया।
- व्यक्तिगत दुर्घटना की पात्रता में 18 से 60 वर्ष की आयु की शर्त को समाप्त किया गया है, जिससे अब दुर्घटना होने पर सभी किसानों को मुआवज़ा दिया जाएगा।
- कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बोर्ड के माध्यम से किसानों के मेधावी बच्चों के लिये छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना में पात्रता के लिये आय सीमा दो लाख रुपए रखी गई थी। इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपए प्रति वर्ष किया गया है।

रायपुर और हल्द्वानी कॉलेज में सबसे पहले शुरू होगी जियो फेंसिंग हाजिरी

चर्चा में क्यों ?

18 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में सबसे पहले जियो फेंसिंग से हाजिरी देहरादून के रायपुर पीजी कॉलेज और हल्द्वानी के एमबी पीजी कॉलेज में शुरू होगी। प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश के तमाम दुर्गम इलाकों तक के डिग्री कॉलेजों में बायोमीट्रिक या रजिस्टर पर हाजिरी हमेशा से ही विवादों में रही है। कहीं बायोमीट्रिक मशीनें काम नहीं करतीं तो कहीं रजिस्टर पर बाद में प्रोफेसर एक साथ हाजिरी लगा देते हैं। छात्रों की हाजिरी अभी तक केवल रजिस्टर पर ही होती आई है। इसमें बदलाव करने के लिये ही प्रदेश सरकार ने जियो फेंसिंग से हाजिरी की कवायद शुरू की है।
- इसके तहत जो भी शिक्षक या छात्र कॉलेज परिसर में प्रवेश करेगा तो उसके मोबाइल से ही उसकी हाजिरी लग जाएगी। इसके लिये मोबाइल जियो फेंसिंग के दायरे में आना ज़रूरी है।
- पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरुआत देहरादून के मालदेवता रायपुर स्थित राजकीय पीजी कॉलेज और हल्द्वानी स्थित एमबी पीजी कॉलेज में होगी। यहाँ जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। पायलट सफल होने के बाद अन्य कॉलेजों में इसे लागू किया जाएगा।
- विदित है कि जियो फेंसिंग सैटेलाइट आधारित प्रणाली है, जिसमें एक विशेष क्षेत्र की जियो फेंसिंग यानी बाउंड्री बना दी जाती है। इस दायरे में जो भी डिवाइस आएगी, वह रिकॉर्ड में आ जाएगी। जियो फेंसिंग के भीतर आने पर ही मोबाइल का वह ऐप काम करेगा, जो कि इससे संबंधित होता है।

नोट :

- जब कोई छात्र या शिक्षक अपने मोबाइल के साथ कैंपस में प्रवेश करेंगे तो उन्हें इसमें डाउनलोड किया गया हाजिरी का ऐप खोलना होगा। यह ऐप केवल कॉलेज के भीतर, यानी जियो फेंसिंग दायरे में आने पर ही काम करेगा। इस ऐप को खोलने के बाद एक ओटीपी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। इसे फीड करेंगे तो ही हाजिरी लग सकेगी। जैसे ही छात्र, शिक्षक उस कैंपस से बाहर जाएंगे तो उनका रिकॉर्ड स्वत: ही अपडेट हो जाएगा।
- गौरतलब है कि इससे पहले परिवहन निगम अपने सभी बस अड्डों पर इसे लागू कर चुका है, जिसके तहत बस अड्डे की जियो फेंसिंग की गई है।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को मिला अटल निर्मल नगर पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

19 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थित मुख्य सेवक सदन में स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले निर्मल नगरों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर प्रदेश के नौ निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पाँच निकायों को स्वच्छ गौरव सम्मान प्रदान किया।
- मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अटल निर्मल नगर पुरस्कार की राशि एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए की जाएगी। इसमें नियमानुसार कैंट क्षेत्रों को भी शामिल किया जाएगा।
- उन्होंने यह भी घोषणा की कि पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत मकान का आवंटन होने के बाद लाभार्थियों को घर का सामान खरीदने के लिये पाँच-पाँच हज़ार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
- उन्होंने बताया कि कि केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री में चारधाम यात्राकाल में काम करने वाले पर्यावरण मित्रों को भोजन, गरम वर्दी के लिये अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। वहीं, निकाय केंद्रीयकृत सेवा के कर्मचारियों के पेंशन देयकों के भुगतान को राज्य वित्त आयोग से एक प्रतिशत की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।
- कार्यक्रम में देहरादून नगर निगम, मुनि की रेती नगर पालिका और नंदप्रयाग नगर पंचायत को स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन पर प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया।
- इसके अलावा नगर निगम हरिद्वार, कैंट बोर्ड लंढौर, नगर पालिका रामनगर, डोईवाला और नरेंद्रनगर को स्वच्छता गौरव सम्मान दिया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दून कैंट स्वच्छता चौपाल का लोगो भी लॉन्च किया।

टिहरी झील में पहली बार होगी नेशनल वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, ऋषिकेश के अध्यक्ष व निदेशक आरके विश्नोई ने बताया कि भारत सरकार के सहयोग व भारतीय ओलंपिक संघ, उत्तराखंड ओलंपिक संघ और आईटीबीपी की तकनीकी देखरेख में 28 से लेकर 30 दिसंबर तक राज्य की टिहरी झील में राष्ट्र स्तरीय केनोइंग और क्याकिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- आरके विश्नोई ने बताया कि पहली बार आयोजित इस राष्ट्र स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में एशियाई चैंपियनशिप एवं ओलंपिक क्वालीफाइंग चौथी रैंकिंग और केनो (डोंगी) स्प्रिंट सीनियर पुरुष और महिला चैंपियनशिप के तहत सभी मुकाबले होंगे।
- तीनदिवसीय इस प्रतियोगिता में देश के 17 राज्यों के 300 खिलाड़ी, जिनमें 200 पुरुष और 100 महिला खिलाड़ी शामिल हैं, ने पंजीकरण कराया है।

नोट :

- गौरतलब है कि करीब आठ साल बाद समुद्र तल से 840 मीटर की ऊँचाई पर केनोइंग और क्याकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
- भारत सरकार के प्रेरित करने पर टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड केनोइंग और क्याकिंग को बढ़ावा देने के लिये टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन करने जा रहा है।
- विश्नोई ने बताया कि उत्तराखंड में राष्ट्र स्तरीय वॉटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता कराए जाने से पर्यटकों और खिलाड़ियों का रुझान बढ़ेगा। टिहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स की अपार संभावनाएँ हैं।
- टिहरी झील और नदियों में वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियाँ बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। टीएचडीसीआईएल प्रतियोगिता के बाद वॉटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों और इससे संबंधित रोज़गारों को लेकर युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना पर भी काम कर रहा है।
- टीएचडीसीआईएल के कॉरपोरेट संचार विभाग के अपर महाप्रबंधक एएन त्रिपाठी ने बताया कि इससे पूर्व कश्मीर में भी इतनी ही ऊँचाई पर कैनोइंग और क्याकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हिमाचल में भी ऊँचाई वाले क्षेत्रों में ऐसी प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।

उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा नई हाइड्रो पावर पॉलिसी की मंज़ूरी सहित लिये गए कई महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नई हाइड्रो पावर पॉलिसी सहित 20 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट की बैठक में नई हाइड्रो पावर पॉलिसी की मंज़ूरी से प्रदेश की नदियों, नालों और खालों से करीब 20 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता का दोहन करने की राह आसान हो गई है। नीति हिमाचल प्रदेश की जलविद्युत नीति 2022 के अनुरूप बनाई गई है।
- इस नीति से अब प्रदेश में जहाँ नए निवेशकों को 25 लाख रुपए की जगह सिर्फ एक लाख रुपए विकास शुल्क देना होगा तो वहीं पुरानी अटकीं योजनाओं को दूसरी कंपनियों को ट्रांसफर किया जा सकेगा। परियोजना की खुदाई के दौरान निकलने वाले माल से ही निर्माण कार्य कर सकेंगे, स्टोन क्रशर भी लगा सकेंगे।
- प्रोजेक्ट की अवधि उसके संचालन से मानी जाएगी। 25 मेगावाट तक के सभी प्रोजेक्ट का यूपीसीएल को अनिवार्य पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीपी) करना होगा।
- राज्य कैबिनेट द्वारा लिये गए कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय -
  - कैबिनेट ने औद्योगिक उत्पादों को बाहर ले जाने के लिये उत्तराखंड लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को मंज़ूरी दे दी। इससे गोदामों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी), कोल्ड स्टोरेज, औद्योगिक संपदाओं, क्लस्टरों से रेल-सड़क कनेक्टिविटी जैसे नए और मौजूदा लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे को मज़बूती मिलेगी। पर्वतीय-मैदानी क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंध मज़बूत होंगे। वेयर हाउस बनाने की राह आसान होगी।
  - कैदियों को अब परिजनों की बीमारी, मृत्यु व पुत्र-पुत्री के विवाह के लिये 15 दिन की पैरोल डीएम के स्तर से मिल सकेगी। पहले मंडलायुक्त को यह अधिकार था। इसके लिये कैबिनेट ने उत्तराखंड (बंदियों के दंडादेश का निलंबन, संशोधन) नियमावली को मंज़ूरी दी।
  - प्रदेश के सरकारी और अशासकीय कॉलेजों में 9वीं से 12वीं के सभी वर्ग के छात्रों को आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जाएंगी। इसकी योजना पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इससे करीब एक लाख छात्रों को लाभ मिलेगा।
  - प्रदेश में नि:शक्त व्यक्तियों को भी महिलाओं की तर्ज़ पर अचल संपत्ति, भूखंड व मकान आदि खरीदने पर 25 लाख रुपए स्टांप शुल्क प्रभार पर 25 प्रतिशत की छूट देने का फैसला लिया गया है। यह छूट जीवनकाल में दो बार ही मिलेगी।
  - यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम में संशोधन कर कोर यूनिवर्सिटी करने पर मुहर।
  - 20 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को उद्योगों की आवश्यकता और रुचि के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा।

नोट :

- राज्यों के लिये पूंजीगत निवेश की विशेष सहायता योजना के तहत परिवहन विभाग को कुछ सुधार करने पर आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी। इसके तहत सिटी बसों को मोटरयान कर में शत-प्रतिशत और परिवहन निगम की पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित बसों को छूट 50 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत की गई।
- उत्तर प्रदेश की तर्ज़ पर उत्तराखंड सरकार ने भी रेल भूमि विकास में भू-उपयोग परिवर्तन की शर्त को खत्म कर दिया है। स्थानीय निकाय व प्राधिकरण तालमेल बनाकर रेल विकास योजनाओं में काम करेंगे।
- लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना के तहत 75 करोड़ रुपए के कार्यों की ई-निविदा में केवल एल एंडटीका टेंडर आया है, इसे खोलने की अनुमति।
- औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को मंज़ूरी। इसमें मुख्यत: व्यापार के सरलीकरण और उद्योगों को अनुकूल वातावरण देने के साथ कर्मचारी हितों को भी समयबद्ध तरीके से दिए जाने के संबंध में प्रावधान किये गए हैं।
- उत्तराखंड राजस्व परिषद अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशासनिक) एवं उप राजस्व आयुक्त (प्रशासनिक) सेवा नियमावली 2022 को मंज़ूरी।
- बदरीनाथ और केदारनाथ धाम की तर्ज़ पर अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम और देहरादून के महासू देवता के लिये भी मास्टर प्लान बनेंगे।
- उत्तराखंड के विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट की मंज़ूरी।

उत्तराखंड राज्य पार्किंग (स्थल चयन, निर्माण एवं संचालन इत्यादि) नियमावली, 2022 को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में पार्किंग की समस्या दूर करने के लिये उत्तराखंड राज्य पार्किंग (स्थल चयन, निर्माण एवं संचालन इत्यादि) नियमावली, 2022 को मंज़ूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड राज्य पार्किंग (स्थल चयन, निर्माण एवं संचालन इत्यादि) नियमावली, 2022 के अंतर्गत राज्य में अब खेती की ज़मीन पर भी खुली पार्किंग बन सकेगी। इसके लिये न तो लैंड यूज बदलने की ज़रूरत होगी और न ही कोई अन्य सरकारी अड़चन आएगी।
- इस नीति के तहत चार श्रेणियों में पार्किंग के निर्माण होंगे। शासन स्तर से सरकारी जमीनों पर पार्किंग बनेगी। निजी ज़मीनों पर कोई भी व्यक्ति पार्किंग का निर्माण कर सकेगा। सरकारी जमीनों पर निजी विकासकर्त्ता भी पार्किंग का निर्माण कर सकेगा, वहीं निजी ज़मीनों पर सरकार पार्किंग का निर्माण कर सकेगी।
- राज्य में जो भी पार्किंग बनाएंगे, उन्हें पाँच साल तक एक रुपया प्रति यूनिट की दर से बिजली में छूट मिलेगी। उनसे सरकार सब डिविजनल चार्ज या डेवलपमेंट चार्ज भी नहीं लेगी। स्थानीय युवा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोज़गार योजना के तहत लोन लेकर भी पार्किंग निर्माण कर सकेंगे।
- अगर कोई होटल, रेस्तरां, अस्पताल या कॉलेज अपनी पार्किंग अन्यत्र बनाता है तो उसे नियमों का पालन करने के साथ ही उस पार्किंग का एक हिस्सा सार्वजनिक पार्किंग के लिये भी रखना होगा, ताकि बाहर से आने वाले लोग यहाँ वाहन पार्क कर सकें।
- राज्य में सभी शहरों में पार्किंग स्थल के चयन और वहाँ वसूले जाने वाले टैरिफ के लिये संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में पुलिस अधीक्षक या उनका नामित सदस्य, नगर नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, अपर ज़िलाधिकारी प्रशासन, स्थानीय निकाय से मुख्य नगर अधिकारी या अधिशासी अधिकारी, यातायात निरीक्षक, अग्निशमन अधिकारी शामिल होंगे।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में पर्यटन सीजन में पार्किंग पर्याप्त न होने की वजह से मसूरी और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों पर लंबे जाम लग जाते हैं। लोग घंटों जाम से जूझने के बाद या तो लौट जाते हैं या किसी तरह आगे बढ़ पाते हैं। पार्किंग नीति आने के बाद इतनी पार्किंग हो जाएंगी कि लोगों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी नहीं होगी।
- विदित है कि राज्य में करीब 300 प्रतिशत की दर से वाहनों कि संख्या बढ़ रही हैं। राज्य गठन के समय तीन लाख 63 हज़ार 916 वाहन थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर करीब 28 लाख 80 हज़ार 520 पहुँच गई हैं। इसमें निजी वाहनों की संख्या ही करीब 26 लाख से अधिक है।

नोट :

प्रदेश में जल्द लागू होगी रूफ गार्डनिंग प्रोत्साहन योजना

चर्चा में क्यों ?

20 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के वन मुख्यालय के मंथन सभागार में बताया कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रूफ गार्डनिंग की अपार संभावनाएँ हैं। इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये सरकार रूफ गार्डनिंग योजना को संचालित करने जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में लगातार कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। इसके कारण ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर की छतों पर रूफ गार्डनिंग के जरिए जैविक सब्जी उत्पादन के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।
- सरकार ने रूफ गार्डनिंग के लिये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून को चुना है। जल्द ही इस योजना को प्रदेश भर में लागू किया जाएगा।
- रूफ गार्डनिंग को बढ़ावा देने के लिये 25 दिसंबर, 2022 से 2 जनवरी, 2023 तक प्रदेश में रूफ गार्डनिंग सप्ताह मनाया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि रासायनिक उर्वरकों व पेस्टीसाइड के उपयोग से लोगों को रसायन मुक्त सब्जी नहीं मिल रही है, लेकिन रूफ गार्डनिंग से लोग अपने घर की छतों पर अपनी जरूरत के लिये जैविक तरीके से सब्जी उत्पादन कर सकते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी लाभकारी होगा।
- प्रदेश के उद्यान निदेशक डॉ. एचएस बवेजा ने बताया दिल्ली के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है, जहाँ पर रूफ गार्डनिंग योजना को संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
- देहरादून की मुख्य उद्यान अधिकारी मीनाक्षी जोशी ने बताया कि रूफ गार्डनिंग में विभिन्न प्रकार के सब्जी उत्पादन के साथ-साथ वर्टिकल गार्डनिंग (उर्ध्व खेती) एवं हाइड्रोपोनिक्स (मिट्टी रहित खेती) का लाभ भी उठाया जा सकता है।

राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

22 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के अपर सचिव विधायी महेश कौशिबा ने बताया कि राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंज़ूरी दे दी है। राजभवन की मुहर लगने के बाद अब अधिनियम राज्य में प्रभावी हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- अपर सचिव महेश कौशिबा ने विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति की पुष्टि करते हुए कहा कि अब राज्य में संशोधन कानून प्रभावी हो गया है। धर्मांतरण विरोधी यह कानून उत्तर प्रदेश से भी सख्त है।
- उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 को मंज़ूरी दी गई थी।
- संशोधन कानून के तहत अब प्रदेश में जबरन या प्रलोभन देकर या धोखे से धर्मांतरण कराने या करने पर 10 साल तक की सजा होगी। नए कानून में 50 हज़ार रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
- सामूहिक धर्मांतरण के मामले में अब तीन से दस साल तक की सजा होगी, पहले अधिकतम तीन साल की सजा का प्रावधान था। साथ ही पीड़ितों को कोर्ट के माध्यम से पाँच लाख रुपए की प्रतिपूर्ति भी मिल सकेगी।
- प्रदेश में धर्मांतरण का कानून अब संज्ञेय व गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएगा। पहले यह असंज्ञेय अपराध था।

देहरादून में जुटेंगे सुरंग निर्माण से जुड़े दुनिया के 600 विशेषज्ञ

चर्चा में क्यों ?

22 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि हिमालयी क्षेत्र में सुरंग निर्माण की संभावनाओं को तलाशने के लिये अगले वर्ष 17 से 21 अप्रैल तक देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार होगा, जिसमें सुरंग बनाने और उसकी डिज़ाइन व तकनीक से जुड़े 148 देशों के 600 से ज़्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि देहरादून में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में विशेषज्ञों द्वारा टनल की एडवांस डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन विषय पर चर्चा की जाएगी।
- इस सेमिनार में केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ इंडियन रोड कॉन्ग्रेस व परमानेंट इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ रोड कॉन्ग्रेस (पीआईआरसी), इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन (आईटीए) सहयोगी रहेंगे।
- सेमिनार में 148 देशों के इंजीनियरों, विशेषज्ञों और सुरंग निर्माण से जुड़ी ख्यातिलब्ध कंपनियों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाएगा।
- इस सेमिनार में 17 व 18 अप्रैल को बैठकें होंगी। 19 से 20 अप्रैल को सेमिनार होगा। 21 अप्रैल को विभिन्न देशों के प्रतिनिधि टेक्निकल विजिट करेंगे।
- उन्होंने बताया कि इस आयोजन से उत्तराखंड को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। वहीं, प्रतिभागियों को ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और ऑलवेदर रोड परियोजना के तहत बन रहीं सुरंगों के साथ ही प्रमुख पर्यटक स्थलों की सैर कराई जाएगी।
- सेमिनार के दौरान दुनिया के दूसरे मुल्कों में सुरंग निर्माण में इस्तेमाल हो रहीं मशीनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
- गौरतलब है कि उत्तराखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पर्वतीय है। राज्य में टनल निर्माण से पर्वतीय क्षेत्र में आवागमन आरामदायक व सुलभ बनाने और यात्रा का समय कम करने का प्रयास हो रहा है। राज्य को टनल निर्माण की नवीनतम तकनीक की जानकारी मिलेगी।
- विदित है कि वर्तमान में रेलवे विकास निगम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच 125 किमी. लंबी रेलवे लाइन बना रहा है। इसमें 105 किमी. लंबाई में टनल बनाई जा रही है। पर्यटन व आर्थिक विकास के लिहाज से यह अत्यंत लाभदायक है।
- ज्ञातव्य है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मसूरी टनल का शिलान्यास मार्च में किया जाएगा।

प्रदेश में एक हज़ार गाँव बनेंगे सोलर ग्राम

चर्चा में क्यों ?

22 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड की ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश में नई सौर ऊर्जा नीति बन रही है, जो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर लागू हो जाएगी। इसके अंतर्गत एक हज़ार गाँवों को सोलर गाँव घोषित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि प्रदेश सरकार राज्य में सूरज की रोशनी से सबसे ज़्यादा समय लबरेज रहने वाले गाँवों में बिजली पैदा करेगी। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी(उरेडा) की टीमें हर ज़िले में ऐसे गाँवों को चिह्नित कर रही हैं, जहाँ सूरज की रोशनी अधिकतम समय रहती है। ऐसे 1000 गाँवों का चिह्निकरण शुरू कर दिया गया है।
- जो भी गाँव सोलर ग्राम घोषित होंगे, वहाँ सोलर प्रोजेक्ट लगाने वालों को सरकार विशेष रियायतें देगी। उन गाँवों में होने वाले बिजली उत्पादन को ग्रिड तक ले जाने के लिये भी खास कार्ययोजना बनाई जाएगी।
- इससे 2000 मेगावाट से अधिक बिजली उत्पादन की राह आसान हो जाएगी।

उत्तराखंड के पाँच अफसरों को मिला उत्कृष्ट ज़िलाधिकारी सम्मान

चर्चा में क्यों ?

25 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के देहरादून में सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से.नि.) ने चारधाम यात्रा के सफल प्रबंधन सहित विभिन्न उल्लेखनीय कार्यों के लिये प्रदेश के पाँच ज़िलाधिकारियों को उत्कृष्ट ज़िलाधिकारी पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया।

प्रमुख बिंदु

- इस कार्यक्रम में हरिद्वार के ज़िलाधिकारी विनय शंकर पांडे को कोविड लॉकडाउन के बाद शुरू हुई काँवड़ यात्रा के सुचारु प्रबंधन के लिये, नैनीताल के ज़िलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को पर्यटन के क्षेत्र में रोज़गारपरक योजनाओं, पौड़ी के ज़िलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान को बेडू के उत्पादों, रुद्रप्रयाग के ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित को पर्यटन को बढ़ावा देने एवं चमोली के ज़िलाधिकारी हिमांशु खुराना को चारधाम यात्रा के सफल प्रबंधन के लिये पुरस्कृत किया गया।

नोट :

- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बताया कि ज़िला प्रशासन सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिये सबसे अहम सीढ़ी है। पुरस्कृत होने वाले ज़िलाधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सजग होकर एवं ईमानदारी के साथ दूर करने में अहम भूमिका निभाई है।
- राज्यपाल ने बताया कि सुशासन का उद्देश्य समावेशी और सर्वांगीण विकास तय करना है। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप शासन प्रवाह सुनिश्चित करने के लिये प्रशासन और जनता के बीच प्रत्यक्ष, भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता है।
- राज्यपाल के सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि ज़िलाधिकारियों को अलग से पुरस्कृत करने की पूर्व में कोई व्यवस्था नहीं थी। राज्यपाल ने ज़िलाधिकारियों के उत्कृष्ट प्रयासों के लिये उन्हें पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।
- प्रशासन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि उत्कृष्ट ज़िलाधिकारी पुरस्कार-2022 के लिये ज़िलों से आवेदन मांगे गए थे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति के सामने ज़िलाधिकारियों ने प्रस्तुतीकरण दिया। राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद पुरस्कार के लिये ज़िलाधिकारियों का चयन किया गया।
- इन उपलब्धियों की वजह से ज़िलाधिकारियों को किया गया पुरस्कृत-
- हरिद्वार के ज़िलाधिकारी विनय शंकर पांडेय ने कोविड लॉकडाउन के बाद शुरू हुई काँवड़ यात्रा का सुचारु प्रबंधन किया। घाटों की सफाई के लिये चलाए गए अभियान की वजह से हरिद्वार को गंगा टाउन में सर्वश्रेष्ठ स्थान हेतु राष्ट्रपति ने भी पुरस्कृत किया था।
- नैनीताल के ज़िलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने सामूहिक जनभागिता के साथ नए प्रयोग करते हुए कई क्षेत्रों में उपलब्धियाँ हासिल कीं। सेब उत्पादन को लेकर उनके प्रयास एवं पर्यटन के क्षेत्र में रोज़गारपरक योजनाओं को ज़िले में लागू करने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है।
- पौड़ी के ज़िलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान पूर्व में जब पिथौरागढ़ ज़िले में तैनात थे, तब उनके बेडू के उत्पादों के लिये महिला स्वयं सहायता समूह के साथ किये गए प्रयासों की प्रधानमंत्री ने अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में सराहना की थी।
- रुद्रप्रयाग के ज़िलाधिकारी मयूर दीक्षित को पर्यटन को बढ़ावा देने, दूर-दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार एवं वर्तमान में भव्य केदारपुरी के पुनर्निर्माण को सही गति से संचालित करने के लिये सराहा जा रहा है।
- चमोली के ज़िलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम एवं हेमकुंड साहिब की यात्रा का सफल प्रबंधन किया। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों को समय पर व सुचारु रूप से पूरा करवाने में भी उनकी अहम भूमिका रही।

हेलीकॉप्टर से पर्यटक कर सकेंगे अब हिमालय दर्शन

चर्चा में क्यों ?

25 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि देश-दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये तथा साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये राज्य में एयरो पर्यटन को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है। एयरो पर्यटन से पर्यटक अब हेलीकॉप्टर से हिमालय के दर्शन कर सकेंगे।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने बताया कि पर्यटन विभाग ने एयरो पर्यटन को बढ़ावा देने को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन सेवा शुरू की है, जिसमें पर्यटक हेलीकॉप्टर से हिमालय की सुंदरता को निहार सकते हैं।
- इसी तर्ज पर पिथौरागढ़ के टनकपुर और बैरागी कैंप ऋषिकेश से हिमालय दर्शन सेवा शुरू करने की तैयारी है। इसके लिये बैरागी कैंप और टनकपुर का चयन किया गया है, जहाँ पर पर्यटक हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमालय के दर्शन कर सकेंगे।
- उन्होंने बताया कि हिमालय दर्शन सेवा के लिये 40 मिनट के टूर पैकेज में प्रति यात्री पाँच हज़ार और डेढ़ घंटे के टूर पैकेज में 10 हज़ार प्रति यात्री किराया निर्धारित किया जा रहा है। इसके लिये हेलीकॉप्टर कंपनियों के साथ वार्ता चल रही है और जल्द ही योजना को शुरू किया जाएगा।

नोट :

आचार्य पं. इंदु प्रकाश को मिला 'लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान'

चर्चा में क्यों ?

26 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पाँचवें अमर उजाला-ग्राफिक एरा ज्योतिष महाकुंभ-2022 के समापन पर ज्योतिषियों को सम्मानित किया। इसके अंतर्गत आचार्य पं. इंदु प्रकाश को विधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये 'लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान' प्रदान किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इससे पहले यह सम्मान सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर बेजन दारूवाला, पं. के.ए. दुबे पद्मेश, वास्तुविद् पं. सतीश शर्मा और आचार्य अजय भांबी को दिया जा चुका है।
- विदित है कि दो-दिवसीय अमर उजाला-ग्राफिक एरा ज्योतिष महाकुंभ-2022 का शुभारंभ 25 दिसंबर को हुआ था।

मुख्यमंत्री को मिला 'स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान-2022'

चर्चा में क्यों ?

27 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री स्व. नित्यानंद स्वामी के 94वें जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नित्यानंद स्वामी जन सेवा समिति द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 'स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान, 2022' से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संगीत, शिक्षा, उद्योग, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक संपदा से जुड़े व्यक्तियों को भी सम्मानित किया।
- उन्होंने बताया कि प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी ने अंत्योदय के विचार को अपने कार्यों के माध्यम से सिद्ध किया और राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किये।
- कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने पद्मश्री बसंती बिष्ट, जितेंद्र जोशी, हरेंद्र कुमार गर्ग, डॉ. डीएम काला, प्रेम हिगवाल को सम्मानित किया। उत्तराखंड गौरव सम्मान रस्किन बांड एवं प्रसून जोशी को दिया गया था। उनकी अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधियों ने यह सम्मान ग्रहण किया।

सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित करेगा एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की का 'स्वस्थ गर्भ' एप

चर्चा में क्यों ?

27 दिसंबर, 2022 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की के प्रोफेसर के.के पंत ने बताया कि आईआईटी रुड़की के शोधकर्त्ताओं ने 'स्वस्थ गर्भ'स्मार्टफोन एप बनाया है। इस एप को नई दिल्ली के एम्स की मदद से तैयार किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रोफेसर के.के. पंत ने बताया कि 'स्वस्थ गर्भ'स्मार्टफोन एप गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व और रियल टाइम (तुरंत) चिकित्सा उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह विशेषकर उन क्षेत्रों की महिलाओं के लिये लाभकारी है, जहाँ चिकित्सा सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। गर्भावस्था के लिये यह पहला एप है, जो तुरंत डाक्टर की सलाह सुनिश्चित करता है।
- उन्होंने बताया कि यह क्लिनिकली प्रमाणित होने के साथ विश्वसनीय भी है। एप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एप का लाभ मरीज और डाक्टर दोनों निःशुल्क ले सकते हैं।
- गौरतलब है कि आईआईटी रुड़की के बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग विभाग के शोधार्थी साहिल शर्मा और प्रो. दीपक शर्मा ने दिल्ली एम्स की प्रो. वत्सला डधवाल और प्रो. अपर्णा शर्मा के सहयोग से 'स्वस्थ गर्भ'एप तैयार किया है।
- एप में गर्भावस्था से जुड़े सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे- हर क्लिनिकल टेस्ट का रिकार्ड रखना और समय पर दवा लेना।
- प्रोफेसर के.के. पंत ने बताया कि 'स्वस्थ गर्भ'एप के लाभों को सामने रखने वाला एक शोध पत्र प्रतिष्ठित 'पीयर-रिव्यू आईईईई जर्नल आफ बायोमेडिकल एंड हेल्थ इंफार्मेटिक्स' में प्रकाशित किया गया है।

नोट :

- आईआईटी रुड़की के बायो साइंसेस और बायो इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर दीपक शर्मा ने बताया कि नवजात मृत्यु दर का अधिक होना गंभीर चिंता की बात है। इसके मद्देनज़र विकसित स्वस्थ गर्भ मोबाइल एप सभी गर्भवती महिलाओं को रियल टाइम चिकित्सा सहायता देगा और गर्भावस्था में माँ-शिशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करेगा। इसके साथ ही, यह प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन को आगे ले जाने में मदद करेगा।
- दिल्ली के एम्स में डीन (रिसर्च) प्रो. रमा चौधरी ने बताया कि 'स्वस्थ गर्भ'एप गर्भावस्था की आम समस्याओं के संभावित समाधान में काफी उपयोगी होगा। घर-घर 'स्वस्थ गर्भ' एप पहुँचाकर इसकी मदद से गर्भावस्था में माँ-शिशु का जीवन आसानी से बचाया जा सकता है।
- दिल्ली एम्स के प्रसूति और स्त्री रोग विभाग की प्रो. वत्सला डधवाल ने बताया कि एप के जरिये गर्भवती महिला डॉक्टरों के बीच संवाद होने से गर्भावस्था के बेहतर परिणाम मिलेंगे। पायलट स्टडी से पता चला है कि यह एप गर्भवती महिलाओं के साथ डाक्टर भी इस्तेमाल कर रहे हैं।
- उन्होंने बताया कि एप की उपयोगिता को लेकर 150 गर्भवती महिलाओं का क्लिनिकल आकलन किया गया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि एप से प्रसव पूर्व देखभाल की गुणवत्ता बढ़ी है और समस्याएँ कम हुई हैं। एप पर रजिस्टर्ड महिलाओं के प्रसव पूर्व सलाह के लिये अस्पताल आने की माध्यमिक संख्या में वृद्धि देखी गई और उनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों का बेहतर अनुपालन भी दिखा।
- विदित है कि कोविड-19 महामारी आने के बाद स्वास्थ्य सेवा में टेलीमेडिसिन का महत्त्व बढ़ गया है। वर्तमान में पूरी दुनिया में एक अरब से अधिक लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में स्वस्थ गर्भ एप में चिकित्सा जगत को बदलने और बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने की असीम संभावना है।

राज्यस्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

29 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के उद्घाटन कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता एवं प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को दो करोड़ से लेकर 33 हज़ार रुपए तक के चेक सौंपे।
- खेल महाकुंभ का उद्देश्य खिलाड़ियों को आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिये तैयार करना है। 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। इससे राज्य के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।
- खेल महाकुंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में राष्ट्रीय खेल की शूटिंग प्रतियोगिता के आयोजन के लिये 31.18 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित शूटिंग रेंज का लोकार्पण भी किया।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के न्याय पंचायत स्तर के विजेता खिलाड़ियों को भी अब प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अभी तक इन खिलाड़ियों को सिर्फ प्रशस्ति-पत्र दिया जाता था।
- उन्होंने बताया कि न्याय पंचायत स्तर के प्रथम विजेता को 300, द्वितीय को 200 तथा तृतीय को 150 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा विकासखंड, जनपद और राज्य स्तर पर खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि में भी 40-50 फीसदी बढ़ोतरी भी की गई है। ब्लॉक स्तर पर विजेता खिलाड़ी को 300 की जगह अब 500 रुपए दिये जाएंगे। वहीं, दूसरा स्थान पाने वाले को 200 की जगह 400 और तृतीय को 150 के बदले 300 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- इसी प्रकार जनपद स्तर पर प्रथम विजेता को 700 के बदले 800 रुपए, द्वितीय को 500 के बजाय 600 और तृतीय को 300 से 400 रुपए दिये जाएंगे। राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले खिलाड़ी को एक हज़ार की जगह 1500, द्वितीय को 600 की जगह 1000 और तृतीय आने वाले खिलाड़ी को 400 रुपए के स्थान पर 700 रुपए दिये जाएंगे।
- उन्होंने बताया कि अभी तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को भोजन के लिये दी जाने वाली धनराशि को 150 रुपए से बढ़ाकर 225 रुपए किया गया है।

नोट :

केंद्र सरकार खरीदेगी उत्तराखंड का मंडुवा

चर्चा में क्यों ?

29 दिसंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में पैदा होने वाला मोटा अनाज (मंडुवा) की खरीद करेगी। उत्तराखंड सरकार ने केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को फसल वर्ष 2022-23 के लिये मंडुवा की खरीद का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि इस फैसले से राज्य के पर्वतीय ज़िलों के किसानों को बहुत फायदा होगा। पहले चरण में 9600 मीट्रिक टन मंडुवा की खरीद की जाएगी। इससे सरकार पर 45 करोड़ का व्ययभार आएगा।
- राज्य में मंडुवा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3574 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। इसके लिये खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, मंडी परिषद, सहकारी समितियों, महिला एवं बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग को आपसी समन्वय से काम करने के निर्देश दिये गए हैं।
- मंडुवा, पौष्टिकता से भरपूर होता है। अब केंद्र सरकार किसानों से मंडुवा खरीदकर मिड डे मील और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बच्चों के साथ अन्य लोगों को इसे उपलब्ध करा सकेगी। इससे राज्य के किसानों की आय में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही स्कूली बच्चों और ज़रूरतमंदों को पौष्टिक आहार भी मिल सकेगा।
- उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पायलेट योजना के तहत दो ज़िलों अल्मोड़ा और पौड़ी के किसानों से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडुवा खरीद योजना लागू की जाएगी। क्रय किये गए मंडुवा को ऊधमसिंहनगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बाँटा जाएगा।
- ऐसे संचालित होगी योजना-
- चारों ज़िलों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लगभग आठ लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।
- प्रतिमाह प्रतिकार्ड एक किलो मंडुवा निशुल्क दिया जाएगा।
- अल्मोड़ा ज़िले में संचालित 20 क्रय केंद्रों और पौड़ी में 11 केंद्रों पर क्रय किया जाएगा।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली से यह लाभार्थियों को बाँटा जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड के पर्वतीय अंचल में उगाया जाने वाला मंडुवा पौष्टिकता का खजाना है। यहाँ की परंपरागत फसलों में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का 85 फीसदी भाग असिंचित होने के बावजूद यहाँ इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। मंडुवा हृदय व मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिये लाभदायक होता है। इसमें पर्याप्त पोषक तत्त्व होने की वजह से यह कुपोषण से बचाने में भी मददगार होता है।

पर्यटन को लेकर देशभर में छाया उत्तराखंड, चारधाम और कांवड़ यात्रा में बना नया रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

30 दिसंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार तीर्थाटन और पर्यटन के क्षेत्र में साल 2022 उत्तराखंड के लिये अच्छा साबित हुआ। कोरोना के बाद फिर से शुरू हुई चारधाम और कांवड़ यात्राएँ चरम पर रहीं। वहीं दो नए रिकॉर्ड भी बने।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार कांवड़ मेला कोरोनाकाल के दो साल बाद हुआ और तीन करोड़ 82 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ से हरिद्वार के व्यवसाय को बूस्टर डोज मिली। चारधाम यात्रा ने भी हरिद्वार के होटल और ट्रैवलर्स व्यवसाय को पटरी पर दौड़ा दिया।
- हरिद्वार की पूरी अर्थव्यवस्था श्रद्धालुओं पर निर्भर है। कोरोनाकाल में हरिद्वार में व्यवसायियों के कर्मचारियों का वेतन तो दूर बिजली-पानी के बिल और बच्चों की स्कूल फीस देने के लाले पड़ गए थे। कोरोना का कहर कम हुआ, लेकिन पाबंदियों से श्रद्धालुओं की संख्या नहीं बढ़ी, लेकिन 14 जुलाई से 27 जुलाई तक हुए कांवड़ मेले ने हरिद्वार के व्यवसाय को बूस्टर डोज दी।

नोट :

- उत्तर भारत के कई राज्यों से तीन करोड़ 82 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में डुबकी लगाई और गंगाजल लेकर गंतव्यों को रवाना हुए। ऐतिहासिक भीड़ के बाद भी मेले में कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस और मेला प्रशासन ने बखूबी मेले को संपन्न कराया।
- कोरोनाकाल के दो साल बाद बिना बंदिशों के चली चारधाम यात्रा ने इस साल नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार चारों धामों में करीब 46 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने दर्शन किये। 19 नवंबर को बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही चारधाम यात्रा का इस साल समापन हो गया था।
- गौरतलब है कि इस बार बदरीनाथ धाम 17 लाख 60 हज़ार 646 श्रद्धालु पहुँचे। वहीं, रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री गंगोत्री धाम पहुँचे। इस बार धाम में 624451 तीर्थ यात्री पहुँचे, जबकि यमुनोत्री धाम में 485635 तीर्थ यात्री दर्शनों के लिये पहुंचे। इस वर्ष केदारनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुँचे हैं, जबकि यात्रा से 211 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है।
- चारधाम यात्रा के दौरान सरकार की ओर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों के बीच विभिन्न कारणों से 281 श्रद्धालुओं की मौत भी हुई। यात्राकाल में स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा मार्गों में नौ स्थानों पर हेल्थ स्क्रीनिंग शुरू की थी।

दृष्टि The Vision

नोट :